माननीय न्यायाधीश महिंदर सिंह सुल्लर के समक्ष,

ईस्ट इंडिया उद्योग लिमिटेड. *-याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य। *—उत्तरदाता*

सीआरआई. 2010 का एम. नं. एम-8765

3 जनवरी 2012

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 482,173(2), 468 - भारतीय दंड संहिता, 1860 - एस.406 - इस आधार पर एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई कि विवाद दीवानी प्रकृति का है - धन की वसूली के लिए मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही - आयोजित, मध्यस्थता कार्यवाही अलग मामला - एफआईआर रद्द करने का कोई कानूनी आधार नहीं - वाणिज्यिक लेनदेन के दौरान कई धोखाधड़ी की गईं - केवल दुर्लभ मामलों में एफआईआर रद्द करना - खारिज।

अभिनिर्धारित किया गया कि यह तथ्य कि याचिकाकर्ता-कंपनी को मध्यस्थ के समक्ष लंबित कुछ पूरी तरह से अलग-अलग लेनदेन से संबंधित एचएसईबी से कुछ राशि वसूलने का हकदार बताया गया है, वास्तव में, इस सिलसिले में वर्तमान एफआईआर (अनुलग्नक पी 1) को रद्द करने का कानूनी आधार नहीं है।

(पैरा 9)

आगे **अभिनिर्धारित किया गया कि** धारा 482 सीआरपीसी के तहत परिकल्पित एफआईआर को रद्द करने के लिए इस न्यायालय का दायरा और अधिकार क्षेत्र एकीकृत नहीं है और अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। कानून का यह सुस्थापित प्रस्ताव है कि यदि केवल पढ़ने पर ही अपराध बनता है, तो रद्द करने का कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। एफआईआर को केवल दुर्लभतम मामलों में ही रद्द किया जा सकता है, अगर यह साबित हो जाए कि प्रतिशोध लेने के लिए इसे दुर्भावनापूर्ण या परेशान करने वाले

तरीके से दर्ज किया गया था और केवल उस स्थिति में, एफआईआर अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, न कि अन्यथा, जिसका वर्तमान मामले में पूर्णतः अभाव है।

(पैरा 17)

याचिकाकर्ता के वकील सुमीत गोयल।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अमित राणा, उप महाधिवक्ता, हरियाणा।

नरेंद्र हुडा, प्रतिवादी नंबर 2 के वकील।

महिंदर सिंह सुल्लर, जे. (मौखिक)

(1) तथ्यों का सार-संग्रह, जिसे तत्काल याचिका में शामिल एकमात्र विवाद को तय करने और रिकॉर्ड से निकलने के सीमित उद्देश्य के लिए आवश्यक उल्लेख की आवश्यकता है, वह यह है कि याचिकाकर्ता ईस्ट इंडिया उद्योग लिमिटेड (संक्षिप्तता के लिए "याचिकाकर्ता-कंपनी") थी विद्युत ट्रांसफार्मर के निर्माण और मरम्मत में लगे हुए हैं। इसने हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड (संक्षेप में "एचएसईबी") को 5000 से अधिक ट्रांसफार्मर की आपूर्ति की। इसमें सामान्य दिनचर्या में गारंटी अवधि के दौरान खामियों को दूर करना था। शिकायतकर्ता दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (संक्षेप में "डीएचबीवीएनएल") (प्रतिवादी नंबर 2) के लगभग 50 ट्रांसफार्मर ख़राब/जले हुए पाए गए और याचिकाकर्ता-कंपनी को दोष दूर करने की आवश्यकता थी। इन ट्रांसफार्मरों की अनुमानित लागत रुपये बताई गई थी। 6 लाख.

(2) डीएचबीवीएनएल के अनुसार, याचिकाकर्ता-कंपनी ने मरम्मत के लिए 14.12.1998 को संकेतित दोषपूर्ण ट्रांसफार्मर उठाए थे, जिन्हें 45 दिनों की अवधि के भीतर चालू हालत में वापस करना आवश्यक था। याचिकाकर्ता कंपनी ने निर्धारित अवधि के भीतर न तो ट्रांसफार्मर की मरम्मत की और न ही उसे वापस किया, जिससे उसे (डीएचबीवीएनएल) को भारी नुकसान हुआ।

(3) विभिन्न प्रकार के आरोप लगाते हुए और घटनाओं का क्रम बताते हुए, कुल मिलाकर, शिकायतकर्ता-डीएचबीवीएनएल ने दावा किया कि याचिकाकर्ता-कंपनी ने उसके साथ धोखाधड़ी की है, अवैध रूप से उसके ट्रांसफार्मर अपने पास रखे हैं, जिनकी न तो मरम्मत की गई और न ही उन्हें वापस किया गया, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। यह स्थिति होने और डीएचबीवीएनएल के शिकायतकर्ता सहायक महाप्रबंधक की शिकायत के मद्देनजर, वर्तमान मामला याचिकाकर्ता-कंपनी के खिलाफ एफआईआर संख्या 650 दिनांक 4.12.2008 (अनुलग्नक पीएल) के माध्यम से दर्ज किया गया था। पुलिस स्टेशन सेक्टर 7, फ़रीदाबाद द्वारा धारा 406 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध किया गया है। जांच पूरी होने के

बाद, पुलिस याचिकाकर्ता-कंपनी के खिलाफ अंतिम पुलिस रिपोर्ट पहले ही पेश कर चुकी है।

(4) मरम्मत करने और ट्रांसफार्मरों को डीएचबीवीएनएल को वापस करने या खुद को मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में सौंपने के बजाय, याचिकाकर्ता-कंपनी सीधे धारा 482 सीआरपीसी के प्रावधानों को लागू करते हुए, एफआईआर (अनुलग्नक पीएल) को रद्द करने के लिए वर्तमान याचिका दायर करने के लिए कूद पड़ी है। , अन्य बातों के अलावा यह दलील देते हुए कि विचाराधीन विवाद दीवानी प्रकृति का है और इस विलंबित चरण में इसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। याचिकाकर्ता-कंपनी के अनुसार, चूँकि इसकी राशि रु. डीएचबीवीएनएल ने 97 लाख रुपये रोक लिए हैं और मामला मध्यस्थ के समक्ष लंबित है, इसलिए, उसे (याचिकाकर्ता-कंपनी को) ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने और वापस करने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त आरोपों के आधार पर, याचिकाकर्ता कंपनी ने यहां पहले बताए गए तरीके से एफआईआर को रद्द करने की मांग की।

(5) उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता-कंपनी की प्रार्थना को खारिज कर दिया और अपने-अपने लिखित बयान दाखिल किए, साथ ही याचिका की पोषणीयता और याचिकाकर्ता कंपनी के अधिकार क्षेत्र पर कुछ प्रारंभिक आपत्तियां दर्ज कीं। दावा किया गया कि जांच पूरी होने के बाद सीआरपीसी की धारा 173 (2) के तहत अंतिम पुलिस रिपोर्ट अदालत में पेश की गई. चूंकि याचिकाकर्ता-कंपनी ने सौंपी गई संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग किया है, विश्वास का उल्लंघन किया है और डीएचबीवीएनएल को धोखा दिया है, इसलिए, एफआईआर को रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है। उत्तरों की संपूर्ण सामग्री को पुन: प्रस्तुत करने के बजाय और पुनरावृत्ति से बचने के लिए, यह कहना पर्याप्त है कि उत्तरदाताओं ने एफआईआर (अनुलग्नक पी 1) में निहित आरोपों को दोहराया है। हालाँकि, यहां यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि उत्तरदाताओं ने याचिका में निहित अन्य सभी आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया है और इसे खारिज करने की प्रार्थना की है।

(6) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने, उनकी बहुमूल्य सहायता के साथ रिकॉर्ड का अध्ययन करने और पूरे मामले पर विचार करने के बाद, मेरे विचार से, इस संबंध में तत्काल याचिका में कोई योग्यता नहीं है।

(7) *पूर्व दृष्टया,* विद्वान वकील का मुख्य तर्क यह है कि याचिकाकर्ता कंपनी को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और चूंकि पार्टियों के बीच कुछ अन्य लेनदेन में राशि की वसूली का मामला मध्यस्थ के समक्ष लंबित है, इसलिए आईपीसी की धारा 406 के तहत दंडनीय कोई अपराध नहीं बनता है। बाल किशन दास बनाम पी.सी.नायर मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के मद्देनजर, यह न केवल योग्यता से रहित है, बल्कि गलत भी है।

(8) जैसा कि स्पष्ट है कि बाल किशन दास के मामले (सुप्रा) में, धान को छीलने के लिए सौंपा गया था और स्टॉक में भारी कमी पाई गई थी। संबंधित समय पर पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौता हुआ था। समझौते की एक शर्त यह थी कि 1.25 किलोग्राम तक की कमी होगी। क्विंटल धान की खरीद की अनुमति दी जानी चाहिए और उस कमी से अधिक, याचिकाकर्ता दरों पर दंड के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगासमझौते में निर्धारित है. मामला मध्यस्थ के पास भेजा गया। मामले की जांच निगरानी विभाग से भी करायी गयी थी. सतर्कता विभाग द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट पर मामला समाप्त कर दिया गया। उस मामले के विशिष्ट तथ्यों एवं विशेष परिस्थितियों में कार्यवाही निरस्त कर दी गयी। संभवतः कोई भी उपरोक्त टिप्पणियों के संबंध में विवाद नहीं कर सकता है, लेकिन मेरे लिए, इस संबंध में वर्तमान विवाद में यह याचिकाकर्ता-कंपनी के बचाव में नहीं आएगा।

(9) जैसा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि डीएचबीवीएनएल ने याचिकाकर्ता-कंपनी को 14.12.1998 को 50 खराब/जले हुए ट्रांसफार्मरों की मरम्मत, खराबी दूर करने और 45 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर वापस करने के लिए सौंपा था। संकेतित ट्रांसफार्मर की अनुमानित लागत रुपये आंकी गई। 6 लाख. याचिकाकर्ता कंपनी ने न तो मरम्मत की और न ही वापस किया बल्कि वास्तव में संपत्ति/ट्रांसफार्मर का दुरुपयोग किया, जिससे डीएचबीवीएनएल को भारी नुकसान हुआ। याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा उक्त हेराफेरी आईपीसी की धारा 405 के तहत परिभाषित आपराधिक विश्वासघात है और धारा 406 के तहत दंडनीय है। केवल तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता-कंपनी को एचएसईबी से कुछ राशि वसूलने का हकदार बताया गया है, जो मध्यस्थ के समक्ष लंबित कुछ पूरी तरह से अलग-अलग लेनदेन से संबंधित है, वास्तव में, वर्तमान एफआईआर (अनुलग्नक पी 1) को रद्द करने का कानूनी आधार नहीं है। यह कनेक्शन.

(10) बात यहीं ख़त्म नहीं होती. तर्क के लिए मान लें (हालांकि स्वीकार नहीं किया गया है), अलग-अलग मामला मध्यस्थ के समक्ष पार्टियों के बीच लंबित है। वर्तमान परिस्थिति में यह बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है. इसी तरह का एक प्रश्न माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजेश बजाज बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली के मामले में तय किया गया था, जिसमें यह देखा गया था कि वाणिज्यिक लेनदेन या धन लेनदेन शायद ही यह मानने का एक कारण है कि इस तरह के लेनदेन से धोखाधड़ी का अपराध समाप्त हो जाएगा। . दरअसल, कई बार व्यापारिक और पैसों के लेन-देन के दौरान भी धोखाधड़ी की जाती है।

(11) फिर से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिसन्स केमिकल इंडस्ट्री बनाम राजेश अग्रवाल और अन्य के मामले में निम्नानुसार कहा गया: -

"9. हम इस तर्क की सराहना करने में असमर्थ हैं कि विवादों को मध्यस्थता के लिए

*संदर्भित करने के लिए समझौते में शामिल प्रावधान एक प्रभावी विकल्प है*विवादित कृत्य अपराध होने पर आपराधिक मुकदमा चलाना। मध्यस्थता समझौते के उल्लंघन से प्रभावित पक्ष को राहत देने का एक उपाय है, लेकिन मध्यस्थ किसी ऐसे कार्य का परीक्षण नहीं कर सकता है जो अपराध की श्रेणी में आता है, भले ही वही कार्य समझौते के तहत किसी भी कार्य के निर्वहन से जुड़ा हो सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा शिकायत को शुरुआत में ही खारिज करने के ये अच्छे कारण नहीं हैं। जांच एजेंसी को आरोपों के पूरे दायरे में जाने और अपने निष्कर्ष पर पहुंचने की आजादी होनी चाहिए थी। इस तरह की जांच को पहले से शुरु करना केवल बहुत गंभीर मामलों में ही उचित होगा जैसा कि हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल 1991(1) आरसीआर (सीएच.) 383: (1992) सप्लीमेंट (1) एससीसी 335) में संकेत दिया गया है" (जोर देने के लिए रेखांकित किया गया है)).

(12) यही विचार माननीय उच्चतम न्यायालय ने गुरचरण सिंह और अन्य बनाम मैसर्स एलाइड मोटर्स लिमिटेड और अन्य , पंजाब राज्य बनाम प्रीतम चंद और अन्य मामले में दोहराया था। और इस न्यायालय द्वारा पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य के मामले में भी दोहराया था।

(13) इतना ही नहीं, विद्वान वकील की अगली कमजोर दलील कि इस विलंबित चरण में याचिकाकर्ता-कंपनी के खिलाफ कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता है, फिर से योग्यता का अभाव है। जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, याचिकाकर्ता-कंपनी के खिलाफ गलत विनियोग और धोखाधड़ी के सीधे आरोप हैं। याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा किस प्रकार का अपराध किया गया था, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा जिसे मुकदमे के दौरान ट्रायल कोर्ट द्वारा साक्ष्य प्राप्त करने के बाद तय किया जाएगा। जैसा कि हो सकता है, लेकिन हेराफेरी और आपराधिक विश्वासघात का अपराध आईपीसी की धारा 406 के तहत तीन साल की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडनीय है, जबकि धोखाधड़ी का अपराध आईपीसी की धारा 420 के तहत सात साल की कैद और जुर्माने से दंडनीय है। . इसलिए, यदि कोई अपराध तीन साल की अवधि के कारावास से दंडनीय है, तो सीमा का सवाल ही नहीं उठता, जैसा कि धारा 468 सीआर पीसी के तहत परिकल्पित है। इसलिए, याचिकाकर्ता-कंपनी के विद्वान वकील के विपरीत तर्क मौजूदा परिस्थितियों में निरस्त किए जाने योग्य हैं।

(14) इस मामले का एक और पहलू भी है, जिसे अलग नजरिये से देखा जा सकता है. जिस बात पर संभवतः विवाद नहीं किया जा सकता वह यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता आपराधिक प्रक्रिया से

संबंधित कानून का एक संग्रह है। इसके प्रावधानों की व्याख्या निर्माण के सुप्रसिद्ध नियम को ध्यान में रखते हुए की जानी आवश्यक है कि प्रक्रियात्मक नुस्खे पर्याप्त न्याय करने के लिए होते हैं। अध्याय XIV कार्यवाही शुरू करने के लिए शर्तें निर्धारित करता है। धारा 190 में आगे कहा गया है कि एक मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान उन तथ्यों की शिकायत प्राप्त होने पर ले सकता है जो अपराध का गठन करते हैं या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर या पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से जानकारी प्राप्त होने पर या अपनी जानकारी के आधार पर, कि ऐसा अपराध किया गया है. अध्याय XV और XVI में विभिन्न प्रक्रियात्मक प्रावधान शामिल हैं जिनका आपराधिक मामलों में संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा पालन किया जाना आवश्यक है।

(15) इसका मतलब यह है कि, जब एक पुलिस रिपोर्ट सीआरपीसी की धारा 173 की उप-धारा (2) या उप-धारा (8) के तहत मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट को अपना दिमाग पुलिस पर लगाना होता है। रिपोर्ट करना और एक निश्चित दृष्टिकोण रखना कि किसी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अपराध का संज्ञान लेना है या नहीं।

(16) इन प्रावधानों को संयुक्त और सार्थक रूप से पढ़ने पर पता चलेगा कि यदि कोई सामग्री/सबूत नहीं है, तो आरोपी को मजिस्ट्रेट द्वारा बरी कर दिया जाएगा, अन्यथा उसके खिलाफ आरोप तय किया जाएगा और मुकदमा शुरू होगा। वर्तमान मामले में, मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष अंतिम पुलिस रिपोर्ट दायर की गई है, ने अभी तक मामले की योग्यता या अन्यथा पर अपना ध्यान नहीं लगाया है और उस स्थिति में, इस न्यायालय द्वारा सी.आर.पी.सी के धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करके व धर्मात्मा सिंह बनाम हरमिंदर सिंह और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता है।.

(17) इन सबसे ऊपर, धारा 482 सीआरपीसी के तहत परिकल्पित एफआईआर को रद्द करने के लिए इस न्यायालय का दायरा और अधिकार क्षेत्र एकीकृत नहीं है और अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। कानून का यह सुस्थापित प्रस्ताव है कि यदि केवल पढ़ने पर ही अपराध बनता है, तो रद्द करने का कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। एफआईआर को केवल दुर्लभतम मामलों में ही रद्द किया जा सकता है, अगर यह साबित हो जाए कि प्रतिशोध लेने के लिए इसे दुर्भावनापूर्ण या परेशान करने वाले तरीके से दर्ज किया गया था और केवल उस स्थिति में, एफआईआर अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, न कि अन्यथा, जिसका वर्तमान मामले में पूर्णतः अभाव है। इस संबंध में हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल

और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रसिद्ध फैसले पर भरोसा किया जा सकता है, जिसे सो मित्तल बनाम कर्नाटक सरकार के मामले में फिर से दोहराया गया था।

(18) इस प्रकार, यह देखा जाएगा कि यदि हेराफेरी के आरोप की प्रकृति, भौतिक साक्ष्य, कानूनी स्थिति और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता, जैसा कि यहां ऊपर चर्चा की गई है, को एक साथ रखा जाए, तो, मेरे लिए, निष्कर्ष अपरिहार्य और अनूठा है याचिकाकर्ता-कंपनी के खिलाफ रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं और मामले की प्राप्त परिस्थितियों में एफआईआर (अनुलग्नक पीएल) को रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है। उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून का अनुपात "म्यूटैटिस म्यूटैंडिस" वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होता है और मौजूदा समस्या का पूर्ण उत्तर है।

(19) विचार करने योग्य कोई अन्य कानूनी बिंदु, पार्टियों के विद्वान वकील द्वारा न तो आग्रह किया गया है और न ही दबाया गया है।

(20) उपरोक्त कारणों के प्रकाश में, इस प्रकार किसी भी कोण से देखा जाए और गुण-दोष पर और कुछ भी टिप्पणी किए बिना, ऐसा न हो कि यह मुख्य मामले की सुनवाई के दौरान किसी भी पक्ष के मामले को पूर्वाग्रहित कर दे, , तत्काल याचिका को इस प्रकार खारिज किया जाता है क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है ।

(21) यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यहां ऊपर जो कुछ भी देखा गया है, वह किसी भी तरह से मुख्य मामले की योग्यता पर प्रतिबिंबित नहीं करेगा, क्योंकि इसे इस प्रासंगिक दिशा में वर्तमान याचिका पर निर्णय लेने के सीमित उद्देश्य के लिए दर्ज किया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

विनीत कुमार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
झज्जर, हरियाणा